खंड 20 नंबर 1 जनवरी 2024

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

आरआईएस डायरी
-अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

G20 भारत 2023 INDIA

आरआईएस की ओर से नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं

# दक्षिण एशियाई एकीकरण: रुझान और आगे की राह

माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती मीनाक्षी लेखी आरआईएस/40 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही हैं।

इस वर्ष आरआईएस अपनी 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का कीर्तिगान करने के लिए कई उच्च–स्तरीय सम्मेलनों और कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। इस संदर्भ में, नई दिल्ली में 9–10 दिसंबर 2023 को "दक्षिण एशियाई एकीकरण : रुझान और आगे की राह" विषय पर एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। इन चार दशकों में, आरआईएस बौद्धिक योगदानों के पावरहाउस के रूप में विकसित हुआ है, जो क्षेत्रीय सहयोग, ग्लोबल साउथ नेतृत्व और सतत विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उद्घाटन सत्र के दौरान अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने संगठन के प्रभावशाली प्रयासों, सहयोगपूर्ण साझेदारियों तथा दक्षिण एशिया और उससे बाहर के क्षेत्रों के व्यापक हित के लिए सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में इसकी प्रतिबद्ध ता के बारे में विचार–मंथन किया। आरआईएस का उद्देश्य अधिक संयोजित, एकीकृत और समृद्ध भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के साथ इस उत्सव की शुरुआत करना है।

सत्र की अध्यक्षता माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने की। माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि अपनी 40वीं वर्षगांठ मना रहा आरआईएस,एक ऊर्जावान संगठन की तरह है, जो विदेश मंत्रालय को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है। अपने क्षेत्रीय थिंक टैंक के नेटवर्क के साथ मिलकर आरआईएस द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में नीति–निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया संस्कृति और इतिहास में अंतःस्थापित है और आरआईएस, अपने प्रयासों से साझा लोकाचार, मूल्यों और सभ्यता के आधार पर देशों को जोड़ने के सेतु के रूप में कार्य करता है। विकसित हो रही प्रौद्योगिकी और दूरियां उत्पन्न कर सकने वाले भू–राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद आरआईएस संयोजन को समृद्ध करने, लोगों की भलाई और कल्याण में सामूहिक रूप से योगदान देने की दिशा में महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में कार्य करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सांस्कृतिक कनेक्टिविटी से परे, अहम जरूरत इस बात की है कि विस्तारित दक्षिण एशियाई परिवार के समग्र कल्याण में योगदान देने वाली

विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। लोगों और वस्तुओं की आवाजाही संयोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और आरआईएस ने इन विषयों पर कार्यशालाओं के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

संयोजन के अलावा, आरआईएस कर, व्यापार और आर्थिक–वित्तीय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर गहन शोध करते हुए सुविचारित निर्णय लेने के लिए अहम समझ प्रदान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यद्यपि ये प्रयास संयोजन के आर्थिक और ढांचागत पहलुओं में योगदान देते हैं, वहीं सांस्कृतिक संयोजन में निवेश

करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच सहयोग जैसे कदम जनता के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत बना सकते हैं।

सत्र की शुरुआत आरआईएस के महा. निदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने ग्लोबल साउथ के थिंक टैंक के रूप में आरआईएस की 40 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला।

उद्घाटन सत्र में डॉ. फहमीदा खातून, कार्यकारी निदेशक, सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी), बांग्लादेश और डॉ. पारस खरेल, कार्यकारी निदेशक, साउथ एशिया वॉच ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपाल ने विशेष भाषण दिया। मुख्य भाषण प्रोफेसर तेत्सुया वातानाबे, अध्यक्ष, आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता ने दिया। भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैककैफ्रे ने अतिथि भाषण दिया।

आरआईएस और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित पुस्तक के साथ ही साथ आरआईएस द्वारा भी दो स्मारक पुस्तकों का विमोचन किया गया। पुस्तक : 'फोर डिकेड्स ऑफ आरआईएस

: विज़न एंड इवोल्यूशन' में आरआईएस के पूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और महानिदेशकों का योगदान है, जिनमें डॉ. मनमोहन सिंह, राजदूत श्याम सरन, श्री हरदीप सिंह पुरी, प्रोफेसर वी.आर. पंचमुखी और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हैं। पुस्तक: फोर डीकेड्स ऑफ आरआईएस: कॉन्सेप्चुअल एंड मैथॉडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन्स के बारे में

...शेष पृष्ठ 7 पर जारी

# भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना

आरआईएस ने म्यांमार अध्ययन केंद्र, मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल के साथ भागीदारी करते हुए 23 दिसंबर 2023 को मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल में 'भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना' विषय पर एक दिवसीय विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के पहले भाग में मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय के समिति कक्ष में "पूर्वोत्तर में आर्थिक विकास और सीमा पार व्यापारः अनुसंधान और नीतिगत कार्रवाई को मजबूत बनाना" विषय पर चर्चा आयोजित की गई, यह क्लोज्ड डोर आयोजन था। मणिपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट हॉल में संगोष्ठी के दूसरे भाग में व्यापक भागीदारी के साथ "भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना" विषय पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

दोनों सत्रों में विचार–विमर्श का नेतृत्व माननीय विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने किया। उनके साथ आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नाओरेम लोकेंद्र सिंह भी शामिल हुए।

आरआईएस द्वारा विकसित और समर्थित एक प्रमुख मंच नॉर्थ ईस्ट ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एडवोकेसी फाउंडेशन (एनईटीआरए) के

अंतर्गत इस संगोष्ठी में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिष्ठित शिक्षाविद और अनुसंधान विद्वान एकत्र हुए।

चर्चा का मार्गदर्शन करते हुए माननीय विदेश राज्य मंत्री ने एमएसएमई, पर्यटन,

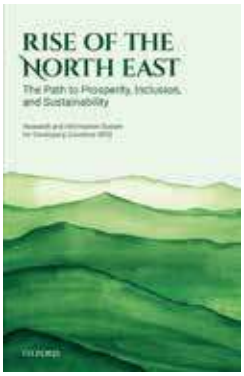


स्वास्थ्य आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्वोत्तर के विकास की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने पूरी तरह कार्यात्मक 19 हवाई अड्डों और अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता सहित हाल के वर्षों में संयोजन में हुई अपार प्रगति का उल्लेख किया। साल 2047 तक विकसित भारत की दूरदर्शिता को साकार के लिए पूर्वोत्तर के विकास को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने सीमा पार व्यापार, सीमांत हाट आदि को बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए एसडीजी हासिल किए जाने का आह्वान किया। क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने एसडीजी और पूर्वोत्तर में सतत विकास; आर्थिक विकास और सीमा पार व्यापार; और विकास का स्थानीयकरण तथा समुदाय

*...शेष पृष्ठ 6 पर जारी*

माननीय विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने पूर्वोत्तर पर आरआईएस पुस्तक का विमोचन किया

# अनुसंधान और नवाचार में तेजी लाने के लिए वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ

जीएएलईआरआई लॉन्च किए जाने के अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के साथ भारत के जी–20 शेरपा श्री अमिताभ कांत।

आरआईएस ने जी–20 सचिवालय, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और इंडोनेशिया सरकार के सहयोग से 26–28 नवंबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दो दिवसीय 'लाइफ इकोनॉमी पर वैश्विक शिखर सम्मेलनः सिद्धांतों से कार्रवाई तक' का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन के आयोजन में जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जीआईजेड), ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी), यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट (यूएनआरआईएसडी), इम्पैक्ट हब और फोर्थ सेक्टर ग्रुप ने सहयोग किया।

इस शिखर सम्मेलन में भारत के जी–20 शेरपा श्री अमिताभ कांत; भारत में इंडोनेशिया की राजदूत महामहिम इना हग्निनिंगत्यास कृष्णमूर्ति; भारत के जी–20 सूस–शेरपा श्री अभय ठाकुर; ब्यूरो फॉर एशिया यूएसएआईडी के सहायक प्रशासक श्री माइकल शिफ़र; ओईसीडी शेरपा डॉ. एंड्रियास शाल; भारत में क्यूबा के राजदूत एच.ई. एलेजांद्रो सिमंकास मारिन; भारत में यूएनडीपी की स्थानीय प्रतिनिधि सुश्री इसाबेल सचान; ब्राज़ील के मिनिस्ट्री ऑफ डेवेलपमेंट, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड के डायरेक्टर, न्यू इकोनॉमीज, श्री लुकास रामाल्हो मैकिएल और अनेक प्रतिष्ठित विचारक, नीति निर्माता तथा उद्योग और सिविल सोसायटी से संबद्ध व्यक्तियों की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही।

इस शिखर सम्मेलन में एकत्र दुनिया भर के विशेषज्ञों और व्यवसायियों ने विकास के एक नए परिप्रेक्ष्यों के रूप में लाइफ इकोनॉमी के मार्गों और टिकाऊ जीवन शैलियों के लिए मूल्यों और नैतिक मानदंडों की भूमिका का अन्वेषण किया। इसमें जी–20 और अन्य देशों के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए सतत उपभोग और उत्पादन, स्थायी खाद्य प्रणालियों, जलवायु और जैव विविधता, एकीकृत और समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के इर्द–गिर्द परस्पर संबंधित क्षेत्रों के बारे में विचार–विमर्श किया गया। इसके अलावा, विकास वित्त और वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार, व्यापार और मूल्य श्रृंखलाओं में बदलाव तथा आकलन के नए परिप्रेक्ष्यों की शुरुआत करके लाइफ इकोनॉमी के उपयोग और उसे सक्षम बनाने के अवसरों के सृजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। यह शिखर सम्मेलन पृथ्वी और यहां के लोगों के अनुकूल–लाइफ इकोनॉमी, के वैश्विक विकास को प्रचारित और प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई योग्य कदमों के साथ संपन्न हुआ।

इस अवसर पर सामाजिक रूप से अधिक समावेशी और पारिस्थितिकीय दृष्टि से टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए अनुसंधान और नवाचार में तेजी लाने के लिए एक नया वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया। जीएएलईआरआई (ग्लोबल एलायंस फॉर लाइफ इकोनॉमीज़ रिसर्च एंड इनोवेशन) नामक नया गठबंधन, अनुसंधान तथा, ज्ञान का सृजन करेगा, और हितधारकों को एक ऐसे विश्व के समान विजन के तहत एकत्र करेगा, जिसमें आर्थिक प्रणालियां किसी को भी पीछे नहीं छूटने देतीं और पृथ्वी पर जीवन के समस्त स्वरूपों की सेवा करती हैं।

जीएएलईआरआई के लॉन्च के अवसर पर, भारत के जी–20 शेरपा श्री अमिताभ कांत

ने कहा कि आज जीएएलईआरआई का लॉन्च जी–20 की भारत की अध्यक्षता के लिए गर्व का क्षण है। पर्यावरणीय क्षरण और अन्य संकटों के कारण यह स्पष्ट हो चुका है कि हमें अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से स्थिरता की ओर उन्मुख करना होगा और समस्त प्रकार के जीवन को तरजीह देनी होगी। भारत के नेतृत्व में जी–20 ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, साथ ही मुझे इस बात की खुशी है कि हमने ओईसीडी और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों सहित दुनिया भर के शोधकर्ताओं और व्यवसायियों का एक गठबंधन तैयार किया है, जो अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से इसे आगे बढ़ाएगा।

ओईसीडी डेवलपमेंट कोऑपरेशन डायरेक्ट्रेट की निदेशक सुश्री मारिया डेल पिलर गैरिडो गोंजालो ने कहा कि जीएएलईआरआई सतत विकास के लिए नवोन्मेषी वित्त और एसडीजी वित्त की राह में आने वाली बाधाओं से निपटने में विकासशील देशों की सहायता करने सहित बढ़ते एसडीजी वित्तपोषण के अंतर को कम करने पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने मदद करेगा। हम अनुसंधान इस प्रयास में भारत, ब्राजील, संयुक्त राष्ट्र, फोर्थ सेक्टर ग्रुप के साथ साझेदारी करके उत्साहित हैं।

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि जीएएलईआरआई का लॉन्च थिंक टैंक, सरकारों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, लोकोपकार, व्यवसाय और सिविल सोसायटी के प्रतिबद्ध वैश्विक समुदाय के बीच सहभागिता, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से 'सिद्धांतों से कार्रवाई' की ओर बढ़ने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। हमे यकीन है कि यह सहयोगपूर्ण प्रयास लाइफ इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे वैकल्पिक मार्गों की तलाश करेगा, जो ग्रह की स्थिरता और जन कल्याण को बढ़ावा देंगे।''

भारत की जी–20 की अध्यक्षता के दौरान जीएएलईआरआई के शुभारंभ में महत्वपूर्ण सहायता देने वाले फोर्थ सेक्टर ग्रुप के सह–संस्थापक और सीईओ श्री हीराद

...शेष पृष्ठ 14 पर जारी

## oychbx] oY;t ,M ykbQLVkbYl] VoMl v U; MoyieV ijkMkbe

इस पुस्तक की रचना अनुभवी विद्वानों और विचारकों के सामूहिक प्रयासों से हुई है, जिन्होंने एक अभूतपूर्व अवधारणा–लाइफः पर्यावरण सम्मत जीवन शैली–के अन्वेषण और उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की यात्रा का आगाज किया है। लाइफ महज एक अवधारणा भर नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है; यह हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहारों में गहन पुनर्विन्यास, स्थिरता, नैतिकता और कल्याण को हमारे आर्थिक मॉडलों के ताने–बाने में एक साथ बुनने का स्पष्ट आह्वान करती है। यह जमीनी स्तर की व्यवहार संबंधी मुहिम से दूरदर्शी आर्थिक मॉडल तक विकसित होने वाले लाइफ में शामिल बहुआयामी पैमानों के व्यापक अन्वेषण का कार्य करती है।

यह पुस्तक भारत में लाइफ की जड़ों से लेकर जी–20 द्वारा इसे विकास पथों में सुधार के मुख्य क्षेत्र के रूप में अंगीकार किए जाने तक इसकी यात्रा की दास्तान बयां करती है। जैसे–जैसे आप इन अध्यायों का अध्ययन करेंगे, आपका सामना लाइफ के परस्पर संबद्ध पहलुओं से होगा, पहला, टिकाऊ उपभोग और उत्पादन की तत्काल आवश्यकता से निपटना, दूसरा, लाइफ के लिए नीतिपरक आधार और नैतिक मूल्य प्रणाली, तीसरा, प्रणालीगत परिवर्तन के लिए नए तौर–तरीके, चौथा, लचीले बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण, और पांचवां, जीडीपी से परे कल्याण के आकलन के नवोन्मेषी दृष्टिकोण। योगदानकर्ताओं ने इस परिवर्तनकारी परिप्रेक्ष्य के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में नैतिक मूल्यों, सामाजिक उद्यमों, प्रौद्योगिकी, वित्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देते हुए लाइफ के मूल सिद्धांतों का अन्वेषण किया है।

इसके अलावा, इसका कथानक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में तेजी लाने में लाइफ की भूमिका को रेखांकित करते हुए आगे बढ़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, जहां विश्व जलवायु परिवर्तन की खतरनाक रफ्तार, बढ़ती असमानता और वैश्विक संबंधों के नैतिक सुधार की आवश्यकता से जूझ रहा है, लाइफ एक टिकाऊ, समावेशी और न्यायसंगत भविष्य की दिशा में एक व्यावहारिक मार्ग के रूप में उभरा है। ■

## भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना

*...शेष पृष्ठ 2 से जारी*

आधारित विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, बुनियादी ढांचे से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों के अलावा, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, डेटा और क्षमताओं को स्वीकार किए जाने जैसे अतिरिक्त मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

माननीय विदेश राज्य मंत्री ने आरआईएस के "राइज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट–द पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी" शीर्षक से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक का भी विमोचन किया। माननीय विदेश राज्य मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर को मिले अद्वितीय प्राकृतिक संसाधनों के उपहार और हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण आर्थिक विस्तार के संदर्भ में हुई प्रगति पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य साझा किया, जो इसके सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षी क्षेत्र होने की ओर इंगित करता है। पूर्वोत्तर भारत का विकास, विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य और अमृत काल की परिकल्पना का हिस्सा है। उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्वोत्तर को विकास इंजन के रूप में उभरना चाहिए और भारत के अन्य हिस्सों के साथ काम करना चाहिए तथा महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दृष्टि से पूर्वोत्तर के सबसे आगे होने के तथ्य के साथ इस क्षेत्र में प्रचुर संसाधन और संभावनाओं से भरपूर प्रतिभाएं मौजूद हैं। माननीय विदेश राज्य मंत्री ने पूर्वोत्तर के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों और एनईटीआरए की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने में आरआईएस के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आरआईएस और म्यांमार अध्ययन केंद्र, मणिपुर विश्वविद्यालय के बीच अधिक औपचारिक सहयोग और समझौता ज्ञापन की भी घोषणा की।

विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों से आमंत्रित शिक्षाविदों और विद्वानों के अलावा, इस संगोष्ठी में मणिपुर विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों, स्थानीय मीडिया और कारोबारियों ने भाग लिया। इंटरैक्टिव सत्र के दौरान कई प्रतिभागियों ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और प्रासंगिक मुद्दों को रेखांकित किया, जिनकी बदौलत कार्यक्रम बेहद सफल रहा। ■

# एफटीए के विश्लेषण हेतु व्यापार प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल कैसे बनाया जाए

आरआईएस ने "एफटीए के विश्लेषण हेतु व्यापार प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल कैसे बनाया जाए" विषय पर एक दिवसीय चर्चा का आयोजन किया। 26 दिसंबर 2023 को चर्चा का उद्देश्य व्यापार संबंधी डेटा की उपयुक्तता पर ध्यान केंद्रित करना था, जो स्थिरता और मानक संबंधी उपायों सहित बातचीत और व्यापार सुविधा उपायों के लिए उपयोगी इनपुट प्रदान कर सके। इस बैठक में यूरोपीय संघ के सीमा पार कार्बन टैक्स पर विस्तार से चर्चा की गई। स्थिरता और व्यापार संबंधों पर गहन अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसका असर ऑटो क्षेत्र के निर्यात पर पड़ सकता है, जो नए स्थिरता मानकों के आने से 15 से 16 फीसदी तक प्रभावित हो सकता है। विचार–विमर्श के दौरान उत्पत्ति के नियम, एफटीए उपयोग का विश्लेषण करने के लिए डेटा के अभाव और इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात का मामला भी चिंता के विषय के रूप में सामने आया। भारत को घरेलू स्तर पर, एचएस 8–डिजिट डेटा पर विस्तृत रिपोर्टिंग; नए मानकों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण के उपायों की पहचान कार्रवाई के लिए प्राथमिकता

वाले क्षेत्रों के रूप में की गई। एफटीए के प्रति नया दृष्टिकोण भारत की व्यापार नीति में नई गतिशीलता ला रहा है, लिहाजा प्रयोगशालाओं, आईसीपी के आधुनिकीकरण जैसे व्यापार संबंधी बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

इस चर्चा की अध्यक्षता आरआईएस के प्रतिष्ठित फेलो श्री राजीव खेर ने की। इस चर्चा के दौरान श्री प्रणव कुमार, उपाध्यक्ष, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डॉ. राजन सुदेश रत्न, उप प्रमुख, यूएन ईएससीएपी; डॉ. प्रीतम बनर्जी, प्रोफेसर और प्रमुख, सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज, आईआईएफटी; डॉ. निशा तनेजा, प्रोफेसर, आईसीआरआईईआर; श्री शशांक प्रिय, सदस्य सीमा शुल्क; श्री अजय श्रीवास्तव, संस्थापक, जीटीआरआई, श्री अतनु गांगुली, उप कार्यकारी निदेशक, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स; और सुश्री पूजा नागपाल, कार्यकारी अधिकारी, एसआईसीएम ने इस विषय के बारे में अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर आरआईएस के वरिष्ठ संकाय सदस्य भी उपस्थित थे। ■

## दक्षिण एशियाई एकीकरणः रुझान और आगे की राह

*...शेष पृष्ठ 2 से जारी*

चर्चा करता है। इनमें बुनियादी आवश्यकता सूचकांक, संरक्षण की प्रभावी दर, एसडीजी गैप इंडेक्स, डेवेलपमेंट कॉम्पैक्ट, एसटीआई के लिए पहुंच, इक्विटी और समावेशन आदि शामिल हैं। आरआईएस–यूनिसेफ खंड पुस्तक 'इन्वेस्टिंग इन अर्ली इयर्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर फ्यूचर रेजीलिएंस : फॉर ऐन इन्क्लूसिव एंड इक्विटेबल वर्ल्ड' प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल की भूमिका के बारे में चर्चा करता है। इसे आरआईएस और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया। इसका विमोचन भी उपरोक्त कार्यक्रम मे हुआ।

वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आरआईएस की भूमिका सिर्फ एक थिंक टैंक के रूप में नहीं, बल्कि सहयोग के प्रेरक के रूप में भी है। आरआईएस का दक्षिण एशियाई एकीकरण तथा संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों, सीपीडी, एसएडब्ल्यूटीईई, एसडीपीआई और ईआरआईए जैसे संगठनों के साथ सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। वक्ताओं ने राष्ट्रों, संगठनों और व्यक्तियों से साझा प्रयासों, समान नीतियों और एकीकृत रणनीतियों के माध्यम से दक्षिण एशिया के भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया।

'दक्षिण एशिया में मैक्रो–अर्थव्यवस्था और आर्थिक अनुकूलन' विषय पर आयोजित पूर्ण सत्र में राष्ट्र के स्तर पर कई चुनौतियों

और उनके क्षेत्रीय प्रभाव जैसे राजकोषीय घाटा, ऋणों में वृद्धि, ऋण की शर्तें, आबादी में वृद्धों की तादाद बढ़ना, कम प्रजनन दर, जनसांख्यिकीय दबाव, महिला श्रम बल की भागीदारी, निर्यात पर निर्भरता, घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को उन्नत बनाना आदि पर चर्चा की गई। 'दक्षिण एशिया में व्यापार और निवेश एकीकरण के रुझान' पर आयोजित पूर्ण सत्र में दक्षिण एशिया के भीतर क्षेत्रीय, उप–क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग के अनुभवों पर प्रकाश डाला गया। इनमें एसएएफटीए कार्यान्वयन की चुनौतियां, उप–क्षेत्रीय परियोजनाओं पर बल, क्षेत्र विशेष से संबंधित रणनीतियां, डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ उठाना और क्षेत्रीय एकीकरण और बुनियादी ढांचे से जुड़े पूर्वोत्तर के विकास के सामर्थ्य की पहचान करना जैसे कदम शामिल हैं। इस दौरान जीवीसी सहित उभरती चुनौतियों और नए अवसरों का भी आकलन किया गया तथा वैश्विक अनिश्चितताओं और दक्षिण एशिया के लिए निहितार्थों पर चर्चा की गई।

इसके अलावा 'दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के विकास और अनुभवों पर विशेष सत्र' को प्रोफेसर दीपक नैय्यर, प्रोफेसर रहमान सोभन, प्रोफेसर मुचकुंद दुबे और राजदूत श्याम सरन ने संबोधित किया। सत्र में पिछले पांच दशकों के दौरान दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के विकास पर विचार–मंथन किया गया। प्रख्यात वक्ताओं ने उन प्रमुख पहलों, हितधारकों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित किया, जिनमें अब तक इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग शामिल रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण एशिया में इतिहास, संस्कृति और जनता के मामले में काफी समानताएं हैं। कार्यक्रम के दौरान साउथ एशिया सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज (एसएसीईपीएस) बोर्ड की बैठक भी आयोजित की गई, जहां सदस्यों ने क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों और पहलों के बारे में विचार विमर्श किया। दक्षिण एशिया नीतिगत मंच के अंतर्गत तीन समानांतर सत्र आयोजित किए गए। एसडीजी और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित सत्र में बहुआयामी निर्धनता से निपटने, जलवायु परिवर्तन और असमानता के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों के बढ़ते महत्व पर चर्चा की गई।

'कृषि मूल्य श्रृंखलाओं' से संबंधित सत्र में कृषि मूल्य श्रृंखलाओं और व्यापार संबंधों की पहचान, नीतिगत हस्तक्षेप, बुनियादी ढांचे के विकास और सुविधा, प्रतिस्पर्धात्मकता, संस्थानों और उद्यमिता जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा विचार विमर्श किया गया।

अंत में महिलाओं के नेतृत्व में विकास विषय पर समानांतर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें निर्णय लेने और नेतृत्वकारी पदों में भागीदारी, रोजगार के अवसरों तक समावेशी पहुंच, डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता तथा स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में निवेश जैसे मुद्दों को शामिल किया गया।

इसके बाद 'एकीकृत दक्षिण एशिया के लिए कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा' पर पूर्ण

सत्र 3 का आयोजन हुआ। इस सत्र में इन पहलों से संबंधित सरोकारों पर गौर करने के साथ–साथ संयोजन और बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इस सत्र में मौजूदा कमियों पर भी प्रकाश डालते हुए उनके शमन के लिए रणनीतियां पेश की गईं तथा संयोजन और बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में सफलता पाने के तरीकों की रूपरेखा तय की गई।

*...शेष पृष्ठ 15 पर जारी*

# त्रिकोणीय सहयोग पर एशियाई सम्मेलन– वैश्विक लक्ष्यों के बारे में सहभागिता का दृष्टिकोण

श्री पेरियासामी कुमारन, ओएसडी (ईआर और डीपीए), विदेश मंत्रालय, भारत उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे हैं।

जीआईजेड ने आरआईएस और जीपीआई की साझेदारी से त्रिकोणीय सहयोग पर पहला एशियाई सम्मेलन (एसीटीआरसी) आयोजित किया। यह सम्मेलन 2–3 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य त्रिकोणीय सहयोग (टीआरसी) के संबंध में बातचीत को बढ़ावा देना और चुनौतियों की पहचान करना तथा सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने की दिशा में टीआरसी के लिए रोडमैप तैयार करना था। अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में विकास के लिए बढ़ते सहयोग के तौर–तरीकों पर चर्चा की गई, जहां एक विकसित देश और एक विकासशील देश अपनी–अपनी विशेषज्ञता के साथ किसी तीसरे विकासशील देश में विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने के लिए संगठित होकर काम करते हैं। इस पद्धति में तीनों साझेदार अपनी–अपनी आवश्यकताओं, अनुभवों, धन और तकनीकी सहायता क्षमताओं के साथ समान योगदान देते हैं। त्रिकोणीय सहयोग पारंपरिक विकास सहयोग की उत्तर–दक्षिण बाधाओं और विकासशील देशों के बीच बढ़ते दक्षिणीय सहयोग से प्राप्त सीख को टालते हुए मौजूदा तौर–तरीकों में से सर्वोत्तम को ग्रहण करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक नया रूप प्रदान करता है। इस सम्मेलन में त्रिकोणीय सहयोग के क्षेत्र में संलग्न दुनिया भर के सौ से अधिक निर्णयकर्ताओं, विशेषज्ञों, व्यवसायियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस सम्मेलन में अनेक लोगों ने ऑनलाइन भाग लिया। आरआईएस का प्रतिनिधित्व कर रहे राजदूत सुधीर टी. देवारे, जीपीआई का प्रतिनिधित्व कर रही सुश्री जियोवाना ज़ोक्कल, और जर्मन सहयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री जूलियस स्पैट्ज़, सम्मेलन में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के टीआरसी परियोजना भागीदारों सहित इस विमर्श में बड़ी तादाद में लोगों के भाग लेने वाले से उत्साहित थे।

विशेषज्ञों ने गरीबी, भूख और असमानता, सतत ग्रामीण विकास के लिए त्रिकोणीय साझेदारी, असमानताओं में कमी लाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिला उद्यमिता सहित महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण, स्थिरता, पर्यावरणसम्मत जीवन शैली (लाइफ) अर्थव्यवस्था और जैव विविधता से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। चर्चा में टीआरसी के लिए त्रिकोणीय सहयोग और वित्त को बढ़ाने की आवश्यकता की भी पड़ताल की गई।

भारत के विदेश मंत्रालय में विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए) के प्रभारी सचिव श्री पेरियासामी कुमारन ने उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में भारत–जर्मन सहयोग तंत्र की प्रेरणा से भारत और जर्मनी द्वारा बेनिन, कैमरून, घाना, मलावी और पेरू में हाल ही में की गई त्रिकोणीय सहयोग संबंधी पहलों के लिए भागीदार देशों में सतत विकास और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से निरुपित और कार्यान्वित परियोजनाओं को सफल उदाहरण करार देते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने इंगित किया कि अन्य विकासशील देशों द्वारा प्रदर्शित रुचि के अनुरूप कई अन्य पहलें पाइपलाइन में हैं, जिनमें अफ्रीका में मोटे अनाजों पर आधारित परियोजना भी शामिल है।

उन्होंने कहा, ग्लोबल साउथ के प्रति लक्षित इस भारतीय प्रयास में जर्मनी एक विश्वसनीय मित्र है और उन्होंने इस बात की सराहना की कि जर्मनी संबंधित भागीदार विकासशील देशों की सुविधा और इच्छा के आधार पर विकास सहयोग से संबंधित भारतीय दर्शन को समझता है। उन्होंने कहा कि भारत के विकास सहयोग में त्रिकोणीय सहयोग एक महत्वपूर्ण वेक्टर है।

भारत में जर्मनी के राजदूत महामहिम श्री फिलिप एकरमैन ने उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में अफगानिस्तान में अपने कार्यकाल के दौरान त्रिकोणीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उल्लेख किया, जब वर्ष 2006–07 में वह अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के

...शेष पृष्ठ 14 पर जारी

# जी–20 नई दिल्ली घोषणा पत्र और उभरती विश्व व्यवस्था

आरआईएस ने अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई के सहयोग से 15 नवंबर, 2023 को अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में "जी–20 नेताओं का नई दिल्ली घोषणा पत्र और उभरती विश्व व्यवस्था" विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य भारत की जी–20 की अध्यक्षता की सफलता और निष्कर्ष के बारे में विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना था।

तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री आर. एन. रवि ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई और प्रधानमंत्री श्री मोदी के 2047 में विकसित भारत के विज़न को दोहराने के साथ–साथ भारत की जी–20 की अध्यक्षता के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में अपने समृद्ध अनुभव साझा किए। प्रोफेसर आर. वेलराज, कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने विशेष भाषण दिया। माननीय राज्यपाल के अध्यक्षीय भाषण के अलावा, दिन भर के कार्यक्रम के दौरान एसडीजी के संबंध में प्रगति में तेजी लाना; सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता; तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; और जेंडर समानता तथा महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना जैसे विशिष्ट विषयों पर दो समानांतर सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में कई विशेषज्ञों ने प्रस्तुतियां पेश कीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि संगोष्ठी में विशेषज्ञों के साथ विद्यार्थियों की बातचीत और उनके बीच उपर्युक्त विषयों पर समूह चर्चा आयोजित की गई।

माननीय राज्यपाल ने भारत की जी–20 की अध्यक्षता की सफलता को दोहराया और भारत की अध्यक्षता की उपलब्धियों को भारत के साथ–साथ भविष्य में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाने के तरीकों पर रोडमैप साझा किया। जी–20 में अफ्रीकी संघ (एयू) की स्थायी सदस्यता को भारत की जी–20 की अध्यक्षता की प्रमुख उपलब्धियों और ग्लोबल साउथ की राय को व्यक्त करने के प्रयासों में से एक के रूप में रेखांकित किया गया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रयासों और व्यवहार में समग्र रूप से परिवर्तन लाने में मिशन लाइफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। माननीय राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा दुनिया देशों के बीच अत्यधिक आय असमानताओं, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, बार–बार घटित होती प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसी आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में, दुनिया देशों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों के पृथक्करण की साक्षी बनी है। उच्च आर्थिक वृद्धि और विकास पर अत्यधिक ध्यान देने के साथ–साथ संसाधनों की कमी ने भी जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदान दिया है। माननीय राज्यपाल ने जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसका भारत ने जी–20 की अध्यक्षता के तहत मिशन लाइफ के माध्यम से संदेश दिया है, भारत के प्रमुख टीकाकरण अभियान और शेष विश्व में उसकी आपूर्ति की सराहना करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, जनधन–आधार–मोबाइल–जैम ट्रिनिटी और आर्थिक समावेशन के लिए जनता द्वारा इसका व्यापक उपयोग, और महिला–पुरुष समानता और महिलाओं के लिए बेहतर अवसरों के साथ एक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने उन विषयों और उन क्षेत्रों में निष्कर्षों की मजबूती को रेखांकित किया, जिन पर भारत की अध्यक्षता के दौरान चर्चा की गई। इनमें हरित विकास, लाइफ, सर्कुलर इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक जिला एक उत्पाद आदि शामिल हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने भारत की जी–20 अध्यक्षता की सफलता तथा विद्यार्थियों और युवाओं सहित जनता को साथ जोड़ते हुए देश के लगभग 60 शहरों में इसकी व्यापक पहुंच की बात दोहरायी। उन्होंने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि भारत की अध्यक्षता अपने सभी पहलुओं में जनता की अध्यक्षता के रूप में परिवर्तित हो गई। उन्होंने भारत की अध्यक्षता के दौरान मूलभूत रूप से वैश्विक शासन को अधिक सहभागी, समावेशी बनाने और उन्हें घरेलू स्तर क्रियान्वित करने के तरीकों पर मुख्य रूप से जोर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जब दुनिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों से जूझ रही थी, तब भारत अपनी अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा और इसके केंद्रीय बैंक, आरबीआई ने ब्याज दर में वृद्धि नहीं की, जिससे समावेशी आर्थिक विकास को नई गति देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने जी–20 की अध्यक्षता से सतत उपभोग और उत्पादन; सामाजिक उद्यमों का योगदान और सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज की शुरूआत; किफायती दरों पर ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय आदि के क्षेत्रों में नैतिक मूल्यों का महत्व; सकल घरेलू उत्पाद से परे अर्थव्यवस्था का मापन; और नीली अर्थव्यवस्था के पहलू तथा समुद्री सुरक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों का सुझाव दिया जिनकी विद्यार्थियों और शिक्षाविदों द्वारा अन्वेषण पड़ताल की जा सकती है।

समानांतर सत्र में विशेषज्ञों ने स्थिरता, डिजिटल अवसंरचना और सशक्तिकरण जैसे विषयों पर चर्चा की। सत्र के अंतर्गत डॉ. एस. आर. राव द्वारा 'एसडीजी के संबंध में प्रगति पर तेजी लाना' में वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने और वन हैल्थ अप्रोच को लागू करने पर, तथा डॉ. एल. सुंगंती द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का महत्व, कोविड के दौरान छात्रों के समक्ष आई समस्याओं, अंतर को कम करने में प्रौद्योगिकी तक पहुंच के औचित्य और संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गई।

*...शेष पृष्ठ 15 पर जारी*

50ok ,lVhvkÃih Qkje lkoltfud 0;k[;ku

# अमृत काल के दौरान एसटीआई के लिए विजन और रोडमैप

एसटीआईपी फोरम व्याख्यान श्रृंखला (सितंबर 2017 से जारी) की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 50वां एसटीआईपी फोरम सार्वजनिक व्याख्यान, डॉ. रमेश अनंत माशेलकर, एफआरएस, पूर्व महानिदेशक, सीएसआईआर और पूर्व अध्यक्ष, ग्लोबल रिसर्च एलायंस और इंडियन नेशनल साइंस अकादमी द्वारा 21 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में दिया गया। इस व्याख्यान का विषय "विकासशील भारत/75 से विकसित भारत/100 तकः अमृत काल के दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए विजन और रोडमैप" था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, आरआईएस की शासी परिषद के सदस्य और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे में एमेरिटस प्रोफेसर डॉ. शेषाद्रि चारी ने की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक श्री सुनीत टंडन ने संक्षिप्त प्रारंभिक टिप्पणी की, जबकि टीईआरआई की महानिदेशक डॉ. विभा धवन ने समापन वक्तव्य दिया।

डॉ. माशेलकर ने अपने अत्यंत विचारशील और प्रेरणादायक व्याख्यान में पहुंच और समानता से लेकर पोल–वॉल्टिंग और अतिशय तेजी से वृद्धि तक के मुद्दों की पूरी श्रृंखला पर ध्यान दिया और इन सभी में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित किया। उन्होंने इस बात पर भी विचार किया कि क्या हम मौजूदा आय असमानता के बावजूद पहुंच और समानता का जादू उत्पन्न कर सकते हैं; और फिर उन्होंने दलील दी कि नवोन्मेषी तकनीकी समाधानों के विकास और प्रसार से यह बहुत हद तक संभव है। डॉ. माशेलकर ने अपने गांधीवादी इंजीनियरिंग के उस मॉडल की ओर इंगित किया जिसमें एमएलएम (कम संसाधनों से अधिक निष्पादन, अधिक लोगों के लिए)

के मंत्र के माध्यम से हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार संभव हुए हैं। उन्होंने एमएलएम के सिद्धांत का उपयोग करके भारत में उच्च गुणवत्ता वाले हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, मोतियाबिंद नेत्र सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी और कृत्रिम पैरों का क्रमशः 40 गुना, 100 गुना, 20 गुना और 300 गुना सस्ती दरों पर विकास का हवाला दिया। अंजनी माशेलकर इनक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड्स का जिक्र करते हुए, उन्होंने विजेताओं द्वारा विशेष रूप से किफायती स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विकसित किए गए कई नवीन तकनीकी उत्पादों को रेखांकित किया।

डॉ. माशेलकर ने भारत को मिडिल इनकम ट्रैप से बचने के प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया और चार कारणों–घटती प्रतिस्पर्धात्मकता, निष्क्रिय नवाचार, कम उत्पादकता और संस्थागत अक्षमता को जिम्मेदार माना। उन्होंने अतिशय तेजी से वृद्धि हासिल करने के लिए "छलांग लगाने से लेकर पोल–वॉल्टिंग" तक करने का विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने मोबाइल डेटा खपत, रीयल–टाइम लेनदेन और एलईडी पहुंच में अतिशय तेजी से वृद्धि का उदाहरण दिया जो भारत में पिछले 8 वर्षों में हुई है। उन्होंने भारतीय नवोन्मेषी मिश्रण यानी जेएएम ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) का जिक्र किया, जिसके अंतर्गत रिकॉर्ड कम समय में लाखों भारतीयों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी, नीति और सिस्टम डिलीवरी इनोवेशन सभी एक साथ मिलकर आए थे। उन्होंने केवल 18 महीनों में दो अरब से अधिक कोविड–19 वैक्सीन विकसित और प्रशासित करने में भारतीय विज्ञान और नवाचार की उत्कृष्ट भूमिका को भी रेखांकित किया।

इस बात पर विचार करते हुए कि भारत/100 के लिए तकनीकी परिदृश्य क्या होगा, डॉ. माशेलकर ने कहा कि प्रौद्योगिकी दुनिया को बदलने का सिलसिला जारी रखेगी और हमें हर हाल में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह हमें आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत/100 बनाने में मदद करे। ऐसा संभव बनाने के लिए उन्होंने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वों को सामने रखा जिनमें विस्तार, समावेशन, उत्कृष्टता, गति, पैमाना, स्थिरता, डिजिटलीकरण, विकेंद्रीकरण, डीकार्बोनाइजेशन, प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, विश्वास और सबसे बढ़कर प्रेरणा जैसे सिद्धांत शामिल थे।

उन्होंने कहा कि भारत के पास जनसांख्यिकी, विविधता और लोकतंत्र की फायदेमंद स्थिति है और इसका अधिकतम लाभ उठाया जाना चाहिए। अपने समापन भाषण में, डॉ. माशेलकर ने सात प्रमुख विशेषताओं अर्थात संतुलित, सुसंस्कृत, सुविध, समृद्ध, सुशासित, सुरक्षित और स्वानंदी भारत को रेखांकित किया। ■

# यूएनडीपी की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 पर नीतिगत संवाद: भारत के लिए रणनीतियां और विचार

कोविड के बाद के प्रभाव और एसडीजी की प्रगति को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करने वाले उसके बाद के घटनाक्रमों की वास्तविकताओं के तहत, भारत ने अपनी जी–20 की अध्यक्षता के दौरान एजेंडा 2030 को उसके एजेंडे के केंद्र में रखने में महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया और एसडीजी में तेजी लाने के लिए लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली), डीपीआई (डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना) और महिलाओं के नेतृत्व में विकास आदि जैसी परिवर्तनकारी संरचनाओं द्वारा समर्थित एक नई कार्य योजना पर आम सहमति बनाई। इस संदर्भ में, 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हाल ही में लॉन्च की गई एशिया प्रशांत क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 और क्षेत्र में एसडीजी के स्थानीयकरण और उन्हें हासिल करने में तेजी लाने के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करने के लिए एक पैनल चर्चा आयोजित की गई।

सत्र की शुरुआत भारत में यूएनडीपी की स्थानीय प्रतिनिधि सुश्री इसाबेल सचान के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई है और यह वैश्विक जीडीपी में 35 प्रतिशत का योगदान करते हुए एक पावरहाउस बनकर उभर रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 1.5 अरब लोग गरीबी के चंगुल से बाहर निकले हैं, भारत में 2005 के बाद से 250 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।

इसके बाद श्री क्रिस्टोफ़ बाहुएट, एशिया और प्रशांत के उप क्षेत्रीय निदेशक, बैंकॉक रीजनल हब, यूएनडीपी के निदेशक द्वारा यूएनडीपी की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 पर प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने इंटरैक्टिव पैनल सत्र का संचालन किया। डॉ. शमिका रवि, सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी–पीएम); सुश्री यामिनी अय्यर, सीईओ, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, और प्रोफेसर पिनाकी चक्रवर्ती, उपाध्यक्ष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) ने अपने विचारशील विचार प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने स्थानीय शासन के लिए वित्त, विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता और स्थानीय सरकारों के लिए एजेंडा निर्धारित किए जाने से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने समावेशी और निरंतर विकास के लिए महिलाओं और महिला श्रम बल की भागीदारी की भूमिका के बारे में भी चर्चा की।

प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान प्रतिभागियों और वक्ताओं ने रिपोर्ट में शामिल किए गए विशिष्ट विषयों और विचारों तथा चर्चा के दौरान उभरे मुद्दों, विशेष रूप से शहरीकरण, युवा रोजगार और न्यायसंगत संक्रमण पर विचार किया। भारत में यूएनडीपी की वरिष्ठ अर्थशास्त्री सुश्री अमी मिश्रा ने समापन भाषण देते हुए सत्र के विचार–विमर्श का सारांश प्रस्तुत किया तथा मेजबान, सह–मेजबान, वक्ताओं और प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। ■

## जी–20 का विकास का एजेंडा

# फिनटेक, डिजिटल परिवर्तन और व्यवसाय की संभावनाएं

आरआईएस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज के सहयोग से 30 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में " जी–20 का विकास का एजेंडाः फिनटेक, डिजिटल परिवर्तन और व्यवसाय की संभावनाएं; सतत और समावेशी विश्व की ओर अग्रसर" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य लाइफ, नैतिक मूल्य और सतत व्यवसाय; एसडीजी में तेजी लाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं; फिनटेक और वित्तीय समावेशन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की जी–20 की अध्यक्षता के व्यापक पहलुओं को कॉलेज के वाणिज्य और अन्य विषयों के छात्रों के साथ साझा करना था।

भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने आभासी माध्यम से शामिल होकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई तथा भारत के युवाओं को नवाचारी व्यावसायिक प्रथाओं में शामिल करने और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के विज़न में योगदान देने के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने अगले कुछ वर्षों में भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की बात भी दोहराई। दयाल सिंह कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर वी.के. पालीवाल ने अपने स्वागत भाषण में युवाओं की प्रतिभा को निखारने में कॉलेज के प्रयासों तथा व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों में स्थिरता के महत्व को रेखांकित किया। आरआईएस के विजिटिंग फेलो डॉ. पी.के. आनंद ने भारत की जी–20 की अध्यक्षता के पांच प्रमुख परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की जिनमें लाइफ के माध्यम से वैकल्पिक विकास परिप्रेक्ष्य का विज़न, बहुपक्षीय विकास बैंकों का सुधार, भारत द्वारा डिजिटलीकरण को अपनाना, यूपीआई का व्यापक उपयोग, आर्थिक समावेशन में इसकी भूमिका और मोटे अनाजों को बढ़ावा देना तथा अफ्रीकी संघ को जी–20 के स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाना शामिल है। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर धनंजय जोशी ने 2047 में विकसित भारत बनने भारत की की महत्वाकांक्षा और उभरते भू–राजनीतिक माहौल को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विकास के संबंध में उचित शिक्षा और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के महत्व को भी रेखांकित किया।

राजदूत संजय भट्टाचार्य की अध्यक्षता में 'लाइफ, नैतिक मूल्य और सतत व्यवसाय' पर पहले सत्र में जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों तथा व्यवहार में समग्र रूप से बदलाव लाने के लिए परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में लाइफ के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। भारत ने न्यायसंगत परिवर्तन और जलवायु अनुकूलन के लिए लाइफ के माध्यम से ग्लोबल साउथ की दृढ़ प्रतिबद्धता की वकालत की। डॉ. धीरज मित्तल और श्री आशीष कुमार ने पैनलिस्ट के रूप में अपने विचार साझा किए। सतत उपभोग और उत्पादन (एससीपी) पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसायों को विस्तार और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के रास्ते तलाशते हुए स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाकर एससीपी के लिए कदम उठाने की भी आवश्यकता है।

सुश्री नवनीत मानव की अध्यक्षता में 'एसडीजी में तेजी लाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं' पर दूसरे सत्र में डिजिटल परिवर्तन के लाभ और जटिलताओं, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के मॉडल और उनके आधार पर निर्मित डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं, इनकी अनुकूलन क्षमता और उद्योग के सतत विकास में डिजिटलीकरण की भूमिका पर चर्चा की गई। प्रोफेसर रजत कथूरिया और डॉ. मानसी केडिया ने पैनलिस्ट के रूप में अपने विचार साझा किए। पैनल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विशेषकर कोविड महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी की भूमिका पर भी चर्चा की और रोजगार के लिए खतरे के रूप में एआई के बारे में चिंताओं को दूर किया। डीपीआई को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी और सरकारी समर्थन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने विशेष रूप से संसाधन आवंटन, बाजार व्यवहार और डिजिटल पहुंच वितरण के संदर्भ में डिजिटल विकास में नीतिगत विचार मंथन की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्री आशीष कुमार की अध्यक्षता में 'फिनटेक और वित्तीय समावेशन' पर अंतिम तकनीकी सत्र में वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाने वाले डिजिटलीकरण और स्व–रोज़गार करने वाली महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने, लोकल चैंपियन (डिजिटल सखी) की भूमिका और वित्तीय परिदृश्य पर फिनटेक के परिवर्तनकारी प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। सुश्री सोनल शर्मा और डॉ. प्रियदर्शी दाश ने भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति और उभरते रुझानों के बारे में विचार प्रस्तुत किये। फिनटेक, विशेष रूप से एआई आधारित वित्तीय प्रौद्योगिकी के 2030 तक वैश्विक स्तर पर 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है। 89 प्रतिशत के साथ फिनटेक अपनाने की दिशा में अग्रदूत भारत, वैश्विक फिनटेक बाजार के 13 प्रतिशत तक पहुंचकर महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। स्व–रोजगार करने वाली महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देने में लोकल चैंपियनों की भूमिका को स्वीकार किया गया तथा महिला उद्यमियों की स्मार्टफोन तक पहुंच के अभाव को दूर करने के लिए नवोन्मेषी समाधान तलाशने की जरूरत पर जोर दिया गया। पैनल ने डिजिटल मंचों के माध्यम से सुलभ ऋण प्रदान करने में फिनटेक के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में भी चर्चा की। डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता से संबंधित चिंताओं को दूर करते हुए जिम्मेदार फिनटेक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करने की

*...शेष पृष्ठ 13 पर जारी*

# लाइफ और वैश्विक एजेंडा: जी–20 और सीओपी 28 स्थिरता लिंक

आरआईएस ने 6 दिसंबर 2023 को एमिटी यूनिवर्सिटी, दुबई, यूएई में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। 'लाइफ और वैश्विक एजेंडा: जी–20 और सीओपी 28 स्थिरता लिंक' शीर्षक से इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की जी–20की अध्यक्षता की धारणा के अनुरूप आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य सीओपी 28 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के युवाओं, विद्यार्थियों और शैक्षणिक समुदाय के बीच पर्यावरणसम्मत जीवन शैली (लाइफ) के सिद्धांतों का प्रचार करना था।

इस आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य लाइफ के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, जी–20 की सफलता को रेखांकित करना और सीओपी 28 के संदर्भ में स्थिरता के महत्व पर बल देना था। विशेष व्याख्यान में शैक्षणिक समुदाय और युवाओं को एक ऐसे संवाद में शामिल करने का प्रयास किया गया जो न केवल शिक्षित हो बल्कि अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में कार्रवाई के लिए प्रेरित भी करे।

राजदूत मंजीव पुरी तथा जी–20 और सीओपी के क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ श्री

निकोलस बुचौड ने विशेष व्याख्यान दिया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण समझ प्रदान करना और लाइफ, जी–20 के एजेंडे और सीओपी 28 के स्थिरता लक्ष्यों के बीच के संबंधों की गहन समझ को बढ़ावा देना था।

राजदूत मंजीव पुरी और श्री निकोलस बुचौड ने पर्यावरणीय स्थिरता को जी–20 और सीओपी 28 द्वारा निर्धारित व्यापक वैश्विक एजेंडे से जोड़ते हुए जीवन शैली के विकल्पों की भूमिका को प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया। इस दिलचस्प सत्र ने विद्यार्थियों को स्थायी भविष्य हासिल करने की राह में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। इसके बाद आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने और विचारित वैश्विक पहलों के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अनुमति मिली। इस इंटरैक्टिव सहभागिता ने सीखने के अनुभव को और समृद्ध किया और उपस्थित लोगों के बीच आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित किया। आरआईएस और एमिटी यूनिवर्सिटी, दुबई के सहयोगात्मक प्रयासों ने सतत विकास और अधिक टिकाऊ भविष्य को आकार देने में युवाओं और शिक्षा जगत की भूमिका पर जारी विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ■

---

*...शेष पृष्ठ 12 से जारी*

आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया। पैनल का समापन व्यवसायों की स्थापना में माइक्रोफाइनेंस ऋणों के महत्व और सीमा को रेखांकित करते हुए किया गया, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि उद्यमियों को 1 लाख तक सीमित करने से उनके उद्यम के विकास और विस्तार में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए स्व–रोज़गार करने वाली महिला उद्यमियों की सहायता और सशक्तिकरण के लिए इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

सम्मेलन में सामाजिक उद्यमिता के जरिए समावेशी विकास, कौशल विकास, सतत निवेश और भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रभाव के विश्लेषण विषयों पर चार दिलचस्प पेपर पेश किए गए। माननीय संसद सदस्य, राज्यसभा प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने समापन सत्र में विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने जी–20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के फोकस क्षेत्रों और भारत की जी–20 की अध्यक्षता की थीम यानी वसुधैव कुटुंबकम् – एक पृथ्वी, एक परिवार– एक भविष्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत के नेतृत्व में जी–20 की सफलता के बारे में अपने विचार साझा किए। अधिवक्ता सुश्री मोनिका अरोड़ा ने भारतीय संविधान की समावेशिता और भारत की जी–20 की अध्यक्षता के दौरान इसकी झलक तथा स्वामी विवेकानन्द के इन संदेशों को रेखांकित किया कि चाहे कितनी ही कठिन और कठोर परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हों, हर स्थिति का सामना करो। ■

## अनुसंधान और नवाचार में तेजी लाने के लिए वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ

*...शेष पृष्ठ 5 से जारी*

सबेती ने कहा, कि ''विकास के लिए जी–20 नेताओं द्वारा समर्थित समग्र दृष्टिकोण हासिल करने के लिए, 'लाइफ इकोनॉमीज' का रुख किए जाने की आवश्यकता है, जो ऐसी आर्थिक प्रणालियां हैं, जिनमें उत्पादन, उपभोग, वित्त, रोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियां न केवल नुकसान को कम करती हैं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाती हैं, समावेशी विकास, अंतर–पीढ़ीगत निष्पक्षता और समृद्ध वातावरण प्रदान करती हैं, जो जैव–विविधता को प्रोत्साहन देती हैं। हमें उम्मीद है कि यह गठबंधन अगले कुछ महीनों में विकसित होता रहेगा यद्यपि हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि लाइफ इकोनॉमीज के प्रति यह बदलाव कई जगहों पर पहले से ही कैसे हो रहा है। ■

## त्रिकोणीय सहयोग पर एशियाई सम्मेलन (एसीटीआरसी)–वैश्विक लक्ष्यों के बारे में सहभागिता का दृष्टिकोण

*..शेष पृष्ठ 8 से जारी*

लिए भारत के साथ किए गए प्रयासों का हिस्सा थे। उन्होंने विकासशील देशों में इस तरह के सहयोग में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में शामिल करने के संबंध में दो प्रमुख सकारात्मकताओं को रेखांकित किया। सर्वप्रथम, विकास के संबंध में भारत के सशक्त इतिहास और शक्तिशाली उभरते बाजार के रूप में इसकी हाल की भूमिका कई क्षेत्रों में इसकी सफलता के साथ इसकी विकास पहलों के प्रति विश्वास उत्पन्न करती है। दूसरा, भू–राजनीति के अधिक से अधिक कठिन होते जाने के बावजूद, अपनी जी–20 की अध्यक्षता के दौरान सफल निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए भारत की ओर से की गई कुशल बातचीत, भारत को जर्मनी द्वारा अपने त्रिकोणीय सहयोग कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में आदर्श रूप से उपयुक्त बनाती है।

इसके अलावा, इस सम्मेलन ने निरंतर संवाद के मार्ग खोले हैं, जबकि हम एजेंडा 2030 हासिल करने के लिए त्रिकोणीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपनी भाषण में यह बात रेखांकित की। उन्होंने लाइफ के पांच पहलुओं पर जोर दिया:

- विकास का विचार, विकास की परिभाषा और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ इसका अंतर्संबंध, जिसमें एसडीजी–2 (भूख की समाप्ति), एसडीजी–6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), एसडीजी7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा), और एसडीजी–3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) शामिल हैं।
- विकास का संकट, असमानताएं बढ़ाए बिना विकास हासिल करने पर जोर देते हुए वृद्धि और विकास की दुविधा को हल करना। लाइफ उद्योगों के लिए ट्रस्टीशिप और सामाजिक लागत की अवधारणा को रेखांकित करता है।
- विभिन्न देशों और कंपनियों के लिए ब्याज दरों और पूंजी तक पहुंच में असमानताओं को रेखांकित करते हुए ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण में पहुंच, इक्विटी और समावेशन (एईआई) करना।
- वित्तीय प्रथाओं में नैतिक विचारों की आवश्यकता दर्शाते हुए वित्त पोषण में नैतिक मूल्यों का महत्व।
- अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत उपभोग और उत्पादन (एससीपी)। उल्लेखनीय है कि एसडीजी–12 करने और सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए एससीपी आवश्यक है।

सम्मेलन में प्रख्यात वक्ताओं ने महसूस किया कि त्रिकोणीय सहयोग मात्र विकल्प भर नहीं है, बल्कि बाधाओं को दूर करने और एसडीजी की दिशा में प्रगति में तेजी लाने की गतिशील युक्ति भी है। विकास संबंधी सहयोग के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दृष्टिकोण की तुलना में काफी लघु होने के बावजूद, त्रिकोणीय सहयोग विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। यह सभी के लाभार्थ, सभी के योगदान पर आधारित वैश्विक लक्ष्यों को लागू करने के लिए साझेदारी पर बल देने वाले, अनुकूलित तरीके की पेशकश करता है। ■

## डब्ल्यूटीओ पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए बहुपक्षवाद के संबंध में पैनल चर्चा

आरआईएस ने 8 नवंबर 2023 को डब्ल्यूटीओ पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए बहुपक्षवाद के संबंध में पैनल चर्चा का आयोजन किया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति और डब्ल्यूटीओ विशेषज्ञ प्रोफेसर अभिजीत दास ने पैनल चर्चा की अध्यक्षता की। जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (जीआईजीए) की अध्यक्ष प्रोफेसर अमृता नार्लिकर और श्री सुमंत चौधरी, प्रधान सलाहकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति भारतीय उद्योग परिसंघ पैनलिस्ट थे। महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी भी चर्चा में शामिल हुए। ■

## जी–20 नेताओं का नई दिल्ली घोषणा पत्र और उभरती विश्व व्यवस्था

..शेष पृष्ठ 7 से जारी

'सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता' पर सत्र के अंतर्गत प्रोफेसर आर. वेलराज ने स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायसंगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने से जुड़ी वित्तीय बाधाओं के साथ–साथ किफायती तरीके से स्थायी जीवन शैली और व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के तरीकों को भी कवर किया। इस सत्र में डॉ. ए. सुब्रमण्यम राजू द्वारा समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था के दोहन और संरक्षण पर चर्चा और समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और बंदरगाहों के विकास पर सिफारिशें भी शामिल रहीं। 'तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना' पर अगला सत्र डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा, जिसके अंतर्गत डॉ. प्रियदर्शी दाश ने भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति और उभरते रुझानों, डिजिटल परिवर्तन के लाभ और जटिलताओं, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की अनुकूलनशीलता और उद्योग के सतत विकास में डिजिटलीकरण की भूमिका पर विचार प्रस्तुत किए। प्रोफेसर जी.रमेश ने प्रौद्योगिकी नवाचार और समावेशन, जेएएम ट्रिनिटी के बारे में चर्चा की और डिजिटल शिक्षा के अभाव से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला।

'महिलाओं और पुरुषों में समानता तथा सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण' विषय पर अंतिम सत्र महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के तरीकों पर केंद्रित रहा। श्रीमती नम्रता चड्ढा ने महिलाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के तरीके सुझाए। डॉ. वी. गायत्री ने डब्ल्यू–20 सहभागिता समूह के प्रयासों की सराहना करते हुए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह के गठन की आवश्यकता पर बल दिया और जी–20 की भारतीय अध्यक्षता द्वारा महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर ध्यान केंद्रित किया।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समान विषयों पर एक समानांतर समूह चर्चा भी आयोजित की गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी समझ के आधार पर सिफारिशों का एक सेट तैयार किया जो जी–20 के सतत विकास और विकास एजेंडे को बढ़ावा दे सकता है।

सामूहिक चर्चा एवं प्रस्तुतियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को समापन सत्र में अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। अन्ना विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज की डीन, प्रोफेसर डी. एल. सुगंती के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संगोष्ठी का समापन हुआ। ■

## दक्षिण एशियाई एकीकरणः रुझान और आगे की राह

..शेष पृष्ठ 7 से जारी

दक्षिण एशिया में वित्तीय क्षेत्र संबंधी सहयोग पर गोलमेज सम्मेलन को दक्षिण एशिया में केंद्रीय बैंकों के वर्तमान पूर्व प्रमुख/वरिष्ठ अधिकारियों ने संबोधित किया। आरबीआई का प्रतिनिधित्व आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री टी. रबी शंकर ने किया।

वक्ताओं ने वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सहयोग के बढ़ते महत्व और नए अवसरों तथा क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र संबंधी सहयोग में हाल ही में उठाए गए कदमों पर चर्चा की। विचार–मंथन के दौरान क्षेत्र में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों की स्थिरता तथा समावेशी विकास और नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी, हरित बैंकिंग और समान मुद्रा भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने में भूमिका पर भी चर्चा हुई।

समापन सत्र में, वक्ताओं ने दक्षिण एशियाई एकीकरण की यात्रा को रेखांकित करते हुए एकीकरण की दिशा में प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद मामूली आंदोलनों पर गौर किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रगति के बावजूद, विशेषकर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को आगे बढ़ाने के संबंध में चुनौतियां बरकरार हैं। वक्ताओं ने क्षेत्र की सामूहिक पहचान स्थापित करते हुए दक्षिण एशिया क्षेत्र के भीतर सांस्कृतिक, ज्ञान और भावनात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने समापन भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि यह सम्मेलन काफी हद तक राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत आगे तक फैले 'आरआईएस परिवार' को एक साथ लाने का एक प्रयास है तथा आरआईएस के शुरुआती सहकर्मियों, सरहदों के पार और पड़ोस में हमारे सहयोगियों के साथ जुड़ने और आरआईएस की विकास यात्रा के बारे में मंथन करने का अवसर था। ■

## प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

### महानिदेशक

- आईएसआईडी द्वारा नई दिल्ली में 5 अक्टूबर 2023 को आयोजित भारत के औद्योगिक परिवर्तन की ओरः 2047 विजन को साकार करने के लिए एक समावेशी, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र का निर्माण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यापार, प्रौद्योगिकी और औद्योगीकरण पर सत्र की अध्यक्षता की।
- द रॉकफेलर फाउंडेशन और सत्व कंसल्टिंग की सह–मेजबानी में 5 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 'एशियाज़ रोड टू सीओपी 28–पाथवेज़ एंड ऑर्प्यूनिटीज राउंडटेबल इन नई दिल्ली' में क्लोज्ड डोर सेशन को संबोधित किया।
- केरल के तिरुवनंतपुरम में 11–14 अक्टूबर 2023 को गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन (जीआईएफटी) द्वारा नवाचार–संचालित ज्ञान अर्थव्यवस्थाएं और ग्लोबल साउथ में परिवर्तन पर 20वें ग्लोबेलिक्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण दिया।
- अदीस अबाबा, इथियोपिया में 12–13 अक्टूबर 2023 को डीईएसए,/यूएनसीसी द्वारा अफ्रीका में एसटीआई4ए सडीजी रोडमैप्स एंड एक्शन इन अफ्रीका पर आयोजित कार्यशाला में 'एसटीआई संभावनाओं और बहु–हितधारक सहभागिता के आकलन के माध्यम से नवोन्वेषी इको. सिस्टम को मजबूत बनानाः केस स्टडीज और चैंपियंस' पर सत्र में चर्चाकर्ता।
- कोलंबो में 16 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा आयोजित यूनिसेफ साउथ एशिया फॉल रीजनल मैनेजमेंट टीम मीटिंग में मुख्य भाषण दिया।
- नई दिल्ली में 19 अक्टूबर 2023 को आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा आयोजित "मानव कल्याण में मूल्यों और नैतिकता की भूमिकाः जीडीपी से आगे बढ़ने का समय" पर व्याख्यान दिया।
- ओईसीडी द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को जी–20 मंच पर 'एसडीजी का स्थानीयकरण और मध्यवर्ती शहर : सभी के लिए एक सतत शहरी भविष्य की ओर' विषय पर आयोजित (ऑनलाइन) वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक में "भारतीय जी–20 परिणामों को आगे बढ़ाना : सतत विकास के लिए जीवन शैली पर उच्च स्तरीय सिद्धांत" विषय पर सत्र का संचालन किया।
- सिंगापुर में 23 अक्टूबर 2023 को एशिया पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी (एपीएएएसीआई) द्वारा आयोजित "पर्यावरण और न्यायसंगत हरित बदलाव के लिए जीवन शैली के माध्यम से टिकाऊ भविष्य की ओर जी–20 की सिफारिशें" पर मुख्य व्याख्यान दिया गया।
- इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस द्वारा 2–4 नवंबर 2023 को हैदराबाद आयोजित आर. राधाकृष्ण स्मारक व्याख्यान में उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण दिया और पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की।
- येल यूनिवर्सिटी द्वारा 4 नवंबर 2023 को संरचनात्मक परिवर्तन पर आयोजित वैश्विक न्याय कार्यक्रम सम्मेलन में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में 6 नवंबर 2023 को सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस (सीआरबी) द्वारा स्थिरता और समावेशिता के लिए समाधानः नीति, नवाचार और सहयोग पर 10वें वार्षिक स्थिरता सम्मेलन 2023 में स्थिरता और समावेशिता के लिए समाधानः नीति की भूमिका पर पहली उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में वक्ता।
- नई दिल्ली में 6 नवंबर 2023 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सशक्त, सतत, संतुलित और समावेशी विकास विषय पर आयोजित वेबिनार में 'सशक्त और सतत विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के जरिए वित्तीय समावेशन और उत्पादकता के लाभः आगे की राह' विषय पर चर्चा मे भाग लिया।
- नई दिल्ली में 7 नवंबर 2023 को द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) द्वारा आयोजित रोड टू दुबईः फ्रॉम जी–20 टू सीओपी–28 विषय पर एक्ट4अर्थ नेशनल डायलॉग में मुख्य भाषण दिया।
- नई दिल्ली में 9 नवंबर 2023 को नीति आयोग के सहयोग से आईसीआरआईईआर द्वारा आयोजित विकास और हरित विकास के लिए एमडीबी और वैश्विक वित्त तक पहुंच के बारे में कार्यशाला में विषयगत सत्र 3 – हरित निवेश के लिए और अधिक निजी पूंजी का लाभ उठाने के लिए एमडीबीएस को पुनः उन्मुख करना पर सत्र में चर्चा मे भाग लिया।
- एशियाई विकास बैंक संस्थान द्वारा 16 नवंबर 2023 को टी–7 हैंडओवर में वैश्विक स्थिरता एजेंडा पर नई साझेदारियों के अवसर के रूप में टी–7/जी–7 पर आयोजित (ऑनलाइन)–सत्र में चर्चा मे भाग लिया।
- एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) के सहयोग से ब्राजीलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस (सीईबीआरआई) द्वारा 16 नवंबर 2023 को "नए बहुध्रुवीय विश्व में थिंक–टैंक, सतत विकास मध्यस्थ?" विषय पर आयोजित (ऑनलाइन) क्लोज्ड–डोर चर्चा में भाग लिया।
- पश्चिम बंगाल के कर्सियांग में 18 नवंबर 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज (आईएसएसीएस) द्वारा सिलीगुड़ी गलियारे में सुरक्षा की पुनर्कल्पना पर गोलमेज चर्चा में सामाजिक–आर्थिक विकास और सुरक्षा गठजोड़ पर सत्र की अध्यक्षता की।
- जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (जीआईजीए) द्वारा 21 नवंबर 2023 को भारत सप्ताह 2023 में आयोजित (ऑनलाइन) 'भारत की जी–20 की अध्यक्षताः जिम्मेदार नेतृत्व के माध्यम से बहुपक्षीयता को पुनर्जीवित करना' विषय पर सत्र का संचालन किया।
- चीबा, जापान में 23–24 नवंबर 2023, जापान एक्सटर्न ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (आईडीई–जेईटीआरओ) और इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आसियान एंड ईस्ट एशिया (ईआरआईए) द्वारा आयोजित आरआईएन वार्षिक बैठक 2023 में भाग लिया।
- केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में 24–26 नवंबर 2023 को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा आयोजित टाइम फॉर अफ्रीकाः एयू इन द जी–20 ऐट द केप टाउन कन्वर्सेशन्स 2023 सत्र में चर्चा मे भाग लिया।
- नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचार योग्यता और प्रदर्शन में सुधार पर राष्ट्रीय कार्यशाला में 'सीखे गए सबक और नवाचार की सफलता की कहानियों को दोहराना' सत्र में चर्चा मे भाग लिया

तथा 6 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा आयोजित समापन सत्र में भी विचार प्रकट किए।

- नई दिल्ली में 11 दिसंबर 2023 को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ), नई दिल्ली और हबीबी सेंटर, जकार्ता द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत–इंडोनेशियाई भू–राजनीतिः वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास को आगे बढ़ाना पर प्रस्तुति दी।
- जापान इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा 12 दिसंबर 2023 को आयोजित जेईएफ–एशिया पैसिफिक फोरम 2023 में हिंद–प्रशांत क्षेत्र में नई उभरती व्यापार संरचना पर सत्र (ऑनलाइन) में चर्चा मे भाग लिया।
- नई दिल्ली में 13 दिसंबर 2023 को यूएनडीपी द्वारा आयोजित यूएनडीपी क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्टः एशिया प्रशांत क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024– भारत के लिए रणनीतियां/अंतर्दृष्टि पर नीतिगत संवाद का संचालन किया।
- मुंबई में 28 दिसंबर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित वैश्विक अनिश्चितता के बीच लचीले ब्रांड इंडिया के निर्माण पर 10वें एसबीआई बैंकिंग और अर्थशास्त्र सम्मेलन में "भारत के अंतर्गत जी–20 से सबकः ग्लोबल साउथ का उदय" विषय पर विशेष भाषण दिया।

## डॉ प्रियदर्शी दाश

### एसोसिएट प्रोफेसर

- सेंटर फॉर ग्लोबल फाइनेंस, एसओएएस, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन द्वारा 13 दिसंबर 2023 को आयोजित सीजीपी संगोष्ठी में "रेगुलेटिंग फिनटेकः करंट प्रैक्टिसिज एंड इवॉल्विंग नेरेटिव्स" पर आभासी प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 26–28 नवंबर 2023 को आरआईएस द्वारा आयोजित "नीति और विनियमन" और " विकास वित्त में सुधार और वैश्विक वित्तीय संरचना" विषय पर ग्लोबल लाइफ समिट की दो एक्शन लैब्स में चर्चा मे भाग लिया।
- नई दिल्ली में 9 नवंबर 2023 को नीति आयोग और आईसीआरआईईआर द्वारा 'विकास और हरित वृद्धि के लिए एमडीबी और वैश्विक वित्त का आकलन' विषय पर आयोजित कार्यशाला में चर्चा मे भाग लिया।
- नई दिल्ली में 1 नवंबर 2023 को 'समावेशी जी–20 –अफ्रीका का पहलु' विषय पर आयोजित नीति आयोग–ओआरएफ उच्च स्तरीय कार्यशाला में 'स्थायी और अनुकूलित अवसंरचना पर भारत–एयू सहयोग' सत्र में चर्चा मे भाग लिया।
- दयाल सिंह कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) और आरआईएस द्वारा 30 नवंबर 2023 को आयोजित 'जी–20 का विकास का एजेंडाः फिनटेक, डिजिटल परिवर्तन और व्यवसाय की संभावनाएं; सतत और समावेशी विश्व की ओर अग्रसर' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में "फिनटेक और वित्तीय समावेशन" सत्र में चर्चा मे भाग लिया।
- ढाका, बांग्लादेश में 4–5 नवंबर 2023 को आयोजित दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस) के दो सत्रों "मूल्य श्रृंखला और एफडीआई" और "मैक्रोइ. कोनॉमिक सहयोग और समान मुद्रा की संभावना" में चर्चा मे भाग लिया।
- तिरुवनंतपुरम में 11–14 अक्टूबर 2023 को गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, आयोजित 20वें ग्लोबेलिक्स अंत. र्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में "फिनटेक और वित्तीय समावेशन" पर प्रस्तुति दी।

## डॉ भास्कर बालाकृष्णन

### विजिटिंग फेलो

- नेशनल साइंस फाउंडेशन श्रीलंका और श्रीलंका एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस (एसएलएएएस), द्वारा 11 दिसंबर 2023 को आयोजित राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय एकता और मैत्री के लिए प्रबल शक्ति के रूप में विज्ञान कूटनीति पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में "विज्ञान कूटनीति और एशिया प्रशांत क्षेत्र–चुनौतियां और अवसर" विषय पर सत्र में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- सेंटर फॉर चाइनीज स्टडीज, चेन्नई में 21 नवंबर 2023 को 'भारत और चीन में उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की भूमिका' पर व्याख्यान दिया।
- डिप्लो एकेडमी, माल्टा द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को विज्ञान कूटनीति 2023 पर आयोजित ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम में भारत की रु विज्ञान कूटनीति पर व्याख्यान दिया।
- तिरुवनंतपुरम में 22 अक्टूबर 2023 को सोमैया और केआईसी द्वारा जी–20 भारत शिखर सम्मेलन 2023 के आर्थिक परिणामों पर सत्र 4 में रुजी–20 भारत शिखर सम्मेलन 2023 से परे बहुपक्षवाद पर आयोजित संगोष्ठी में अध्यक्ष का आरंभिक भाषण।

## डॉ पी. के. आनंद

### विजिटिंग फेलो

- ओईसीडी द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को जी–20 मंच पर 'एसडीजी का स्थानीयकरण और मध्यवर्ती शहरः जी–20 पीएलआईसी' विषय पर आयोजित (ऑनलाइन) वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, में 6 नवंबर, 2023 को नीति आयोग द्वारा आयोजित एसडीजी पर त्वरित प्रगति कार्यक्रम में भाग लिया।
- आईएसआईडी, नई दिल्ली द्वारा 30 नवंबर 2023 को 'भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन तथा दक्षता और इक्विटी के बीच चल रही होड़' विषय पर आयोजित अनुसंधान संगोष्ठी में भाग लिया।
- द जर्मन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन (डीडब्ल्यूआईएच) नई दिल्ली और जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) नई दिल्ली द्वारा 7 दिसंबर 2023 को आयोजित डिजिटल ट्विन्स ऑफ द ओशन – ऑपर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर प्रूफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भाग लिया।
- आईएसआईडी–आईजीआईडीआर, नई दिल्ली द्वारा 8 दिसंबर 2023 को आयोजित भारत और वैश्विक आर्थिक विकास पर नीतिगत गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
- आईएचडी, नई दिल्ली द्वारा 18 दिसंबर 2023 को आयोजित आईएचडी ग्लोबल कॉन्क्लेव एडवाइजरी कमेटी में भाग लिया। ■

## पुस्तकें और रिपोर्ट्स

☐ **द ग्रैंड सक्सेस ऑफ जी-20 भारत प्रेसीडेंसी,** आरआईएस, नई दिल्ली, 2023.

☐ **जी-20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड्स,** आरआईएस, नई दिल्ली, 2023.

☐ **प्रपेलिंग इंडियाज मैरीटाइम विजन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज,** आरआईएस–सीएमईसी, नई दिल्ली, 2023.

## पत्रिकाएं

☐ **डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू,** खंड–16 संख्या–3, जुलाई–सितम्बर, 2023.

☐ **जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन**, खंड–5 संख्या–2, सितम्बर, 2023.

## आरआईएस चर्चा पत्र

#284: असेसिंग इंडिया–वियतनाम मैरीटाइम ट्रेडः ऐन एम्पिरिकल एक्सप्लोरेशन बाइ प्रबीर डे एंड तुहिनसुभ्रा गिरी

#283: ट्रेडिशनल मेडिसिन इन सार्कः अरीजनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बाइ नम्रता पाठक

**मेकांग गंगा नीतिगत सारांश** संख्या 12, जनवरी, 2023.

## एआईसी कॉमेंट्रीज

☐ संख्या 42: पोटेंशियल ऑफ आसियान–इंडिया पार्टनरशिप इन मैनेजिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, अगस्त 2023.

☐ संख्या 41: फॉर्टी सेकंड आसियान समिटः आउटकम्स एंड फ्यूचर आउटलुक, जुलाई 2023.

## आरआईएस संकाय द्वारा बाहरी प्रकाशनों में योगदान

आनंद, पी.के., और कुमार, के. 2023। "गोइंग बियोंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी): वैल्यूइंग वेलबीइंग"। टी–20 पॉलिसी ब्रीफ. टास्कफोर्स 3. टी–20 इंडिया सचिवालय।

आनंद, पी.के., और कुमार, के. 2023।" फाइनेंसिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल एग्रीफूड सिस्टम्स"। टी–20 पॉलिसी ब्रीफ. टास्कफोर्स 6. टी–20 भारत सचिवालय।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. 'सॉलिडेरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल साउथः इंडियन जी–20 इनिशिएटिव्स'; शर्मा, एन. श्रीवास्तव, ए.; मिश्रा, विवेक कुमार और ठाकरे, भूषण (संपा.) सॉलिडेरिटी फॉर सस्टेनेबिलिटीः कॉमन कन्सर्न्स फॉर ग्लोबल कॉमन्स में डब्ल्यूओएसवाई फाउंडेशनः नई दिल्ली।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "रिमार्क्स" महावर, एन., और भट्टाचार्जी, डी., (संपा) इंडियाज डेवलेपमेंट पार्टनरशिपः एक्सपेंडिंग विस्टाज में, आईसीडब्ल्यूए। पृष्ठ 13–19.

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "सम यूनिक फैसिट्स ऑफ इंडियाज जी–20 प्रेसीडेंसी" किर्टन, जॉन.; और कोच, मेडलिन, (संपा.) इंडिया द न्यू दिल्ली समिट, में। जीटी मीडिया ग्रुप लिमिटेडः यूके। पृष्ठ 42–43.

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "इंडोनेशिया एंड इंडियन जी–20 प्रेसीडेंसीज इन पर्सपेक्टिव" ईस्ट एशिया फोरम क्वार्टरली, खंड 15 संख्या 3 जुलाई–सितंबर 2023. पृष्ठ 17–21.

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. भारत–पश्चिम एशिया–यूरोपीय आर्थिक गलियारा। गतिशक्ति का अन्तरराष्ट्रीयकरण। अमर उजाला, सितंबर। (हिंदी में)।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. क्लोजर लिंक्स, फास्टर ग्रोथ : अ न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर डेक्कन हेराल्ड, 17 सितम्बर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. जी–20 समिट इंडिया : इंडियन इथोज एंड वैल्यूज फॉर ग्लोबल सॉल्यूशन्स। ऑर्गेनाइज़र, 05 सितम्बर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. डेटा बियोंड सर्वेः स्टैटिस्टिकल सिस्टम रिक्वॉयर्स रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट स्टेट–ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज इंडियन एक्सप्रेस, जुलाई।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "स्वदेशी एंड आत्मनिर्भर भारतः कन्ट्राडिक्शन्स, कॉम्प्लीमेंटरीज एंड द वे फॉरवर्ड", महाजन, अश्विनी (संपादित) आत्मनिर्भरः अ स्वदेशी पैराडाइम में रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पृष्ठ 1–17.

डे, प्रबीर, 2023. "अनलॉकिंग द जीवीसी पोटेंशिल्स इन इंडियाः रोल ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन"। टी बी चटर्जी, ए घोष और पी रॉय (संपा.) रिस्क एंड रेजिलिएंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज : एसैज इन ऑनर ऑफ प्रोफेसर अजित्वा रायचौधुरी, स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर।

डे, प्रबीर और अंबुमोझी, वी., 2023. क्रॉस–बॉर्डर एनर्जी ट्रेड एंड डेवलेपमेंट ऑफ बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स (बीईजेड) इन नॉर्थईस्ट इंडियाः टुअर्ड ऐन इंटीग्रेटेड रीजनल प्रोग्राम। अंबुमोझी, वी. और सिंह, के.बी. (संपा.), क्रॉस–बॉर्डर इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स (पृष्ठ 56–96) में। रूटलेज, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर, 2023. "म्यांमार्ज इंटीग्रेशन विद् द वर्ल्डः इमर्जिंग ट्रेन्ड्स एंड वे फॉरवर्ड", आनंद, वी. और वशिष्ठ, सी (संपा.), रीविज़िटिंग म्यांमारः प्रेजेंट थ्रू द पास्ट, में, वीआईएफ और पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर, 2023 (अगस्त)। "व्हॉट केन वी एक्सपेक्ट द ट्वेंटिएथ आसियान–इंडिया समिट टू डिलिवर?", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड 1, संख्या 7

डे, प्रबीर. 2023. (6 सितंबर)। ट्वेंटिएथ आसियान–इंडिया समिटः एक्सपेक्टेशन्स एंड चैलेंजिस", इकोनॉमिक टाइम्स।

डे, प्रबीर 2023. " ट्वेंटिएथ आसियान–इंडिया समिट : की टेकअवेज"। ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड1, संख्या 8.

डे, प्रबीर 2023. "इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसीः द पावर ऑफ प्रोग्रेस", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड1, संख्या 6.

डे, प्रबीर 2023. "इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसीः द पावर ऑफ प्रोग्रेस", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड1, संख्या 6, जुलाई 2023.

तड़स, ए.जी. 2023. 'चूजिंग लाइफ इन जी–20 इंडिया'। किर्टन जे एंड कोच एम (संपा.) में, जी–7 इंडियाः 2023 न्यू दिल्ली समिट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो पृष्ठ. 58–59. ■

## ckY;koLFkk d vkjfFkd o"kk e fuo'k fd, tku dh l[r t:jr

भविष्य के आर्थिक विकास के लिए समूची दुनिया के हर क्षेत्र में बाल विकास को अनुकूलित करने के लिए बाल्यावस्था के आरंभिक वर्षों में निवेश किए जाने की सख्त जरूरत पर केंद्रित है। यह पुस्तक प्रस्तावित करती है कि भविष्य के अनुकूलन में निवेश मौजूदा बाल समूहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उच्चतम मानव पूंजी से युक्त अगली पीढ़ी के बाल समूहों तक फैला हुआ है; इस प्रकार आज के बच्चे अपने जीवनकाल के दौरान अपनी अगली पीढ़ियों की समृद्धि और अनुकूलन को आकार दे सकते हैं।

बच्चों के अस्तित्व, कल्याण और सामाजिक असमानताओं को मिटाने के संदर्भ में अधिक न्यायसंगत दुनिया का निर्माण करने के लिए बाल विकास समावेशी आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक इष्टतम निवेश के माध्यम से बाल विकास के हर पहलू तक पहुंच, समानता और समावेशन का संक्षिप्त उल्लेख करती है। समावेशी मानव–केंद्रित विकास के लिए, पुस्तक विभिन्न मुद्दों, चाहे वह जेंडर और बाल बजट हों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, प्रवासन के प्रभाव, आईटी की भूमिका, मानव पूंजी में सुधार के लिए ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आदि पर गौर करती है।

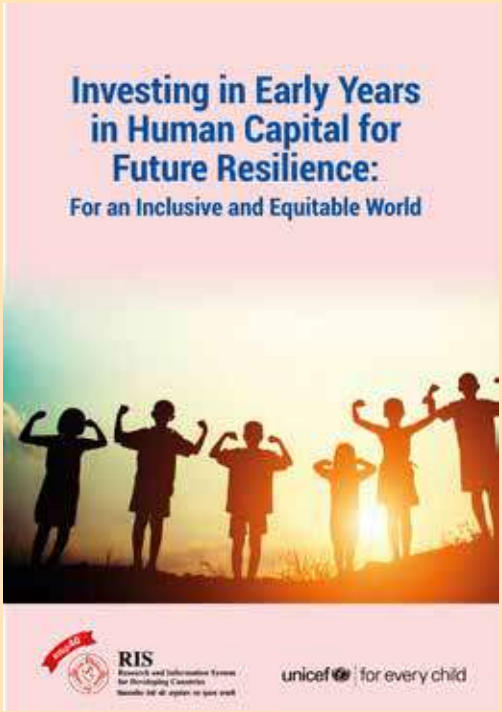


यह पुस्तक इस बारे में वैश्विक स्तर के साक्ष्य–आधारित परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है कि कैसे सुविचारित और एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सभी को समान अवसर प्रदान करते हुए समानता को बढ़ावा और मानव विकास को गति देती है; ताकि महिला–पुरुष समानता, समावेशी विकास और संतुलित आर्थिक विकास को साकार किया जा सके।

वर्ष 2023 में भारत की जी–20 की अध्यक्षता ने इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में काम करने में भारतीय अनुभव से सीखने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया, और जिसकी गूंज अन्य देशों में भी है। पुस्तक के अध्याय, समय रहते मिलकर सही निवेश किए जाने पर दुनिया के बच्चों के भविष्य और समावेशी विश्व अर्थशास्त्र के भविष्य की कहानी बताते हैं।

पुस्तक के 10 अध्याय वर्ष 2030 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने की दिशा में सामाजिक संयोजन, महिला–पुरुष समानता, समावेशी आर्थिक विकास और बच्चों के अधिकारों को साकार करने के लिए देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदान हैं।

पुस्तक के सभी अध्यायों में प्रख्यात शिक्षाविदों ने योगदान दिया है और ये बच्चों के विभिन्न पहलुओं संक्षिप्त उल्लेख करते हैं जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि यह पुस्तक वर्तमान समय में और आने वाले वर्षों में बच्चों के लिए बेहतर परिणाम पाने के लक्ष्य हेतु हमें भारत की जी–20 की अध्यक्षता के थीमः एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की दिशा में सामूहिक प्रयास करने में मदद करेगी। ■

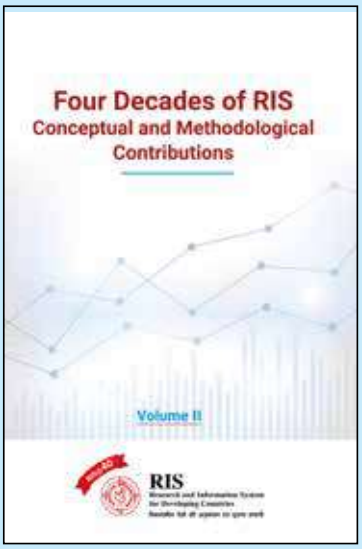


आरआईएस के 40 वर्ष पूरे करने के लिए आरआईएस द्वारा उपरोक्त दो पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। पहली पुस्तक में समय–समय पर आरआईएस के लिए मार्गदर्शक रही विभूतियों के विचार समाहित हैं। इनमें माननीय डॉ. मनमोहन सिंह, श्री एच.एस. पुरी, राजदूत श्याम सरन, राजदूत मोहन कुमार सहित अध्यक्षों; राजदूत एस.टी.देवारे सहित उपाध्यक्षों; प्रोफेसर वी.आर. पंचमुखी, डॉ. नागेश कुमार और डॉ. बिश्वजीत धर सहित महानिदेशकों और पूर्व संकाय सदस्यों और आरआईएस की कार्य योजनाओं से संबद्ध अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का योगदान शामिल है। ये सभी केवल आरआईएस के विकास के साक्षी रहे हैं, बल्कि इन्होंने इसके मार्ग को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कहा. नियां केवल आरआईएस के इतिहास का ही बखान नहीं करतीं, बल्कि सामान्य रूप से पिछले चार दशकों के विकास की कहानी भी बताती हैं।

दूसरी पुस्तक आरआईएस के बौद्धिक आधार–अनुसंधान के क्षेत्र में वर्षों से किए गए इसके प्रयासों को निर्देशित करने वाले वैचारिक ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करती है। आरआईएस ने विकास के क्षेत्र में नीतिगत अनुसंधान की लगातार बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुसंधान की मौजूदा कार्यपद्धतियों और तकनीकों को लगातार अनुकूलित किया है। यह पुस्तक इन पहलुओं का व्यापक अन्वेषण प्रस्तुत करती है, जिससे पाठकों को उन सैद्धांतिक आधारों की गहन समझ मिलती है, जिन्होंने आरआईएस के प्रभावशाली योगदान को बढ़ावा दिया है। ■

RIS
Research and Information System
for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर IV-B, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी मार्ग, नई दिल्ली–110 003, भारत। दूरभाष 91–11–24682177–80
फैक्स: 91–11–24682173–74, ईमेल: dgoffice@ris.org.in
वेबसाइट: www.ris.org.in

*Follow us on:*

www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबन्ध सम्पादक : तीश मल्होत्रा